नवभारत 26 जुलाई 2026

रविवारीय

मध्य प्रदेश की शिक्षा : आधी जीत, आधी चुनौती

डॉ. आशुतोष उपाध्याय

कमध्य प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था इस समय एक अजीब स्थिति में है. एक तरफ ऐसे आँकड़े हैं जिन पर कोई भी राज्य गर्व कर सकता है, दूसरी तरफ ऐसे आँकड़े हैं जो चिंता में डाल देते हैं. दोनों एक ही रिपोर्ट में हैं, एक ही साल के हैं, और दोनों सच हैं. केंद्र सरकार की UDISE+ 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 1 लाख 22 हजार 120 स्कूल हैं, जिनमें से 92 हजार 250 सरकारी हैं. इन स्कूलों में 1 करोड़ 51 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और 7 लाख 17 हजार से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं.

जो अच्छा हुआ- सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षकों की भर्ती है. सिर्फ एक साल में प्रदेश ने 77 हजार 968 नए शिक्षक जोड़े. यह देश के किसी भी बड़े राज्य द्वारा एक साल में की गई सबसे बड़ी नियुक्ति है. इसका सीधा असर दिखा. छात्र-शिक्षक अनुपात 24 से घटकर 21 हो गया, जो देश के पाँच सबसे बड़े राज्यों में सबसे अच्छा है. राष्ट्रीय औसत 24 है. एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 13 हजार 198 से घटकर 7 हजार 217 रह गई. शून्य नामांकन वाले स्कूल 1 हजार 211 से घटकर मात्र 463 बचे. प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट अब शून्य है. लड़कियों का 0.0 प्रतिशत और लड़कों का 0.6 प्रतिशत. राष्ट्रीय औसत 0.3 प्रतिशत है. यह वास्तव में उल्लेखनीय है. सुविधाओं में भी प्रदेश कई मामलों में देश से आगे है. 98.1 प्रतिशत स्कूलों में पुस्तकालय है, राष्ट्रीय औसत 89.5 प्रतिशत. खेल मैदान 94.9 प्रतिशत स्कूलों में, राष्ट्रीय औसत 83 प्रतिशत. दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप 93.1 प्रतिशत स्कूलों में, राष्ट्रीय औसत 79.1 प्रतिशत. और सबसे उत्साहजनक बात, 2026 की बोर्ड परीक्षा में सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया. दसवीं में सरकारी स्कूलों का परिणाम 76.80 प्रतिशत रहा और निजी स्कूलों का 68.64 प्रतिशत. 2022 में स्थिति उल्टी थी, तब सरकारी स्कूल 55.40 प्रतिशत पर थे और निजी 69.48 प्रतिशत पर. चार साल में यह बदलाव छोटा नहीं है.

जो चिंता का विषय है- अब दूसरी तरफ देखिए. प्रदेश में कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 32 बच्चे कक्षा बारहवीं तक पहुँच पाते हैं. राष्ट्रीय औसत 47 है. यह देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे कम है. माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट 16.8 प्रतिशत है, राष्ट्रीय औसत 11.5 प्रतिशत. लड़कों में यह 18.9 प्रतिशत है और लड़कियों में 14.6 प्रतिशत. यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है. आमतौर पर माना जाता है कि लड़कियाँ पढ़ाई छोड़ती हैं. मध्य प्रदेश में उल्टा हो रहा है. हर स्तर पर लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर है. दसवीं से ग्यारहवीं में जाने वाली लड़कियाँ 72.9 प्रतिशत हैं और लड़के 65.2 प्रतिशत. कन्या शिक्षा परिसर, केजीबीवी और छात्रवृत्ति योजनाओं का यह असर है. अब जरूरत लड़कों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की है. नामांकन के आँकड़े और भी गंभीर तस्वीर दिखाते हैं. प्राथमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन दर 63.9 प्रतिशत है, यानी 36 प्रतिशत बच्चे अपनी उम्र के अनुसार सही कक्षा में नहीं हैं. माध्यमिक स्तर पर यह दर 37.3 प्रतिशत है, यानी दस में से चार बच्चे भी सही कक्षा में नहीं हैं.

आदिवासी बच्चों का सवाल- यह प्रदेश की सबसे गंभीर समस्या है. मध्य प्रदेश में कुल छात्रों में 21.7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं, जो किसी भी बड़े राज्य से अधिक है. पर उनकी स्थिति देखिए. देश भर में आदिवासी बच्चों का प्राथमिक नामांकन अनुपात 98.8 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में 78.9 प्रतिशत. माध्यमिक में राष्ट्रीय 81.3 प्रतिशत, प्रदेश में 58.6 प्रतिशत. और उच्चतर माध्यमिक में राष्ट्रीय 51.9 प्रतिशत के मुकाबले प्रदेश में केवल 32.8 प्रतिशत. आदिवासी लड़कों में तो यह आँकड़ा 29.7 प्रतिशत है. यानी ग्यारहवीं-बारहवीं की उम्र के दस में से तीन आदिवासी लड़के भी स्कूल में नहीं हैं. मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और शहडोल में स्थिति सबसे खराब है.

सुविधाओं का असली सच- औसत आँकड़े अच्छे दिखते हैं, पर जब सरकारी और निजी स्कूलों को अलग-

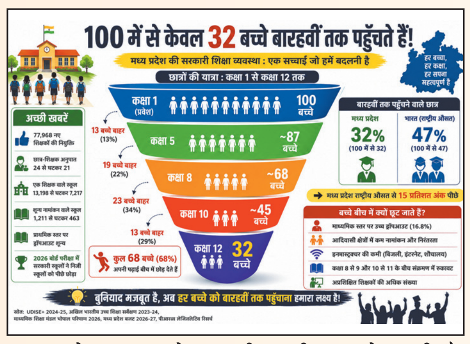

अलग देखा जाए तो असली तस्वीर सामने आती है. अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों में लगभग सभी बुनियादी सुविधाएँ 100 प्रतिशत हैं. सरकारी स्कूलों में नहीं.दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय सरकारी स्कूलों में केवल 13.7 प्रतिशत, अनुदान प्राप्त स्कूलों में 86.6 प्रतिशत. डिजिटल लाइब्रेरी सरकारी में 1 प्रतिशत, अनुदान प्राप्त में 49.1 प्रतिशत. लड़कियों के चालू शौचालय सरकारी में 86.8 प्रतिशत, बाकी सब जगह 100 प्रतिशत. चालू बिजली सरकारी स्कूलों में 85.4 प्रतिशत. बिजली की यह कमी सिर्फ बिजली की कमी नहीं है. जिस स्कूल में बिजली नहीं चलती, वहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट के आँकड़े कागजी रह जाते हैं. इंटरनेट प्रदेश के 45.7 प्रतिशत स्कूलों में है, राष्ट्रीय औसत 63.5 प्रतिशत. यह प्रदेश की सबसे बड़ी डिजिटल खाई है.

नई पहलों की समीक्षा-सरकार ने तीन बड़े कदम उठाए हैं.

संदीपनी विद्यालय- पहले सीएम राइज नाम था, अप्रैल 2025 में भगवान कृष्ण के गुरु आचार्य सांदीपनि के नाम पर इनका नामकरण हुआ. इस समय 369 विद्यालय चल रहे हैं. इनमें स्मार्ट क्लास रूम, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, खेल सुविधाएँ और कला-संगीत के लिए अलग जगह है. परिणाम भी अच्छे हैं. 2026 की बोर्ड परीक्षा में दसवीं के 75.36 प्रतिशत और बारहवीं के 75.10 प्रतिशत छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए. 58 छात्र प्रदेश की मेरिट सूची में आए. बालाघाट के वारासिवनी के एक छात्र ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रतियोगिता 2026 में देश में पहला स्थान पाया. पर एक बात साफ रहनी चाहिए. 369 विद्यालय प्रदेश के 92 हजार 250 सरकारी स्कूलों का मात्र 0.4 प्रतिशत हैं. घोषित लक्ष्य 9 हजार विद्यालयों का है, पर उस तक पहुँचने का बजट रास्ता अभी बजट दस्तावेजों में दिखाई नहीं देता.

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस- जुलाई 2024 में प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक-एक ऐसा महाविद्यालय शुरू किया गया. हर कॉलेज में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र भी बनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. उच्च शिक्षा में प्रदेश का नामांकन 27.7 लाख है, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद देश में चौथे स्थान पर है.

पीएम श्री विद्यालय- केंद्र की इस योजना को देश स्तर पर 2026-27 में लगभग 7 हजार 500 करोड़ रुपये मिले. पर चिंता की बात यह है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में इस योजना का खर्च कभी 60 प्रतिशत से ऊपर नहीं गया, जबकि सर्व-व्यापी समग्र शिक्षा योजना को केवल 50 करोड़ रुपये की मामूली बढ़ोतरी मिली.

आँकड़ों का अंतर- सरकार का दावा है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन 32.4 प्रतिशत बढ़ा है और 2025-26 में कुल नामांकन में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2026-27 के लिए 1.45 करोड़ छात्रों का लक्ष्य रखा गया है. वहीं DISE+ के आँकड़े बताते हैं कि प्रदेश का कुल नामांकन 2021-22 के 1.62 करोड़ से घटकर 2024-25 में 1.52 करोड़ रह गया, यानी लगभग 10 लाख छात्र कम हुए. दोनों आँकड़े अलग-अलग अवधि और संभवत: अलग आधार के हैं. पर इतना बड़ा अंतर अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब शिक्षा विभाग को देना चाहिए.

शिक्षकों का प्रशिक्षण- संख्या बढ़ी, पर गुणवत्ता का सवाल बना हुआ है. माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक 79.5 प्रतिशत हैं, राष्ट्रीय औसत 92.7 प्रतिशत. यह बड़े राज्यों में सबसे कम है. पूर्व-प्राथमिक स्तर पर तो केवल 32.2 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित हैं, राष्ट्रीय औसत 53.3 प्रतिशत. निपुण भारत के तहत बुनियादी साक्षरता के लक्ष्य इसी स्तर पर तय होते हैं. एक असामान्य बात यह भी है कि माध्यमिक स्तर पर पुरुष शिक्षक (77.8 प्रतिशत) महिला शिक्षकों (81.6 प्रतिशत) से कम प्रशिक्षित हैं. देश में आमतौर पर उल्टा होता है.

चुनौती- मध्य प्रदेश ने पिछले चार सालों में जो किया, वह हल्के में लेने लायक नहीं है. शिक्षक आ गए, प्राथमिक ड्रॉप आउट खत्म हो गया, सरकारी स्कूलों के बोर्ड परिणाम निजी स्कूलों से बेहतर हो गए. ये असली उपलब्धियाँ हैं. पर अब चुनौती अलग है. समस्या अब शिक्षक की कमी नहीं है, न ही स्कूल भवन की. समस्या यह है कि बच्चा नौवीं-दसवीं तक आते-आते कहीं खो जाता है. 100 में से 68 बच्चे बारहवीं तक नहीं पहुँचते.

अब क्या किया जाए

पहला- बचे हुए 7 हजार 217 एकल शिक्षक स्कूलों में दूसरा शिक्षक भेजा जाए. 78 हजार नए शिक्षक आए हैं, यह काम अब कठिन नहीं होना चाहिए. शुरुआत आदिवासी जिलों से हो. **दूसरा**- आदिवासी लड़कों के लिए आवासीय माध्यमिक विद्यालय. लड़कियों के लिए केजीबीवी का ढाँचा काम कर रहा है, आँकड़े इसकी गवाही देते हैं. लड़कों के लिए ऐसा कुछ नहीं है. सात सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाले जिलों में यह प्राथमिकता होनी चाहिए. **तीसरा**- सरकारी स्कूलों में शौचालय और बिजली का अभियान. दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय 13.7 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 40 प्रतिशत और लड़कियों के चालू शौचालय 95 प्रतिशत तक ले जाने का तीन साल का लक्ष्य तय हो. **चौथा**- बिजली और इंटरनेट. जिन 14.6 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में चालू बिजली नहीं है, वहाँ सौर ऊर्जा लगाई जाए. भारतनेट से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी दी जाए. **पाँचवाँ**- माध्यमिक शिक्षकों का आपात प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राथमिकता में अप्रशिक्षित पुरुष शिक्षक. **छठा**. कक्षा आठ से नौ और दस से ग्यारह के बीच का संक्रमण. यही वह जगह है जहाँ बच्चे सबसे ज्यादा छूटते हैं. आठवीं से नौवीं में जाने की दर 77.8 प्रतिशत है, राष्ट्रीय औसत 86.6 प्रतिशत. यह अकेला आँकड़ा प्रदेश की सबसे कमजोर कड़ी बताता है.

व्यंग्य

दिल्ली की म्यूजिकल चेयर रेस

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

चेयर रेस नामक खेल से शायद सब ही न केवल परिचित ही होंगे बल्कि अपनी स्कूलिंग के दौरान बचपन में वे इस खेल के प्रतिभागी भी रह चुके होंगे. यह क्या शानदार खेल है. इस खेल को म्यूजिकल चेयर रेस के नाम से भी जाना जाता है. अन्य खेलों के समान इसमें भी प्रतिस्पर्धा और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलता है. इस खेल में सभी प्रतिभागियों की निगाहें उस कुर्सी पर लगी रहतीं हैं उसे जिस पर कब्जा जमाना होता है

जिसने उस पर कब्जा जमा लिया कुर्सी उसी की हो जाती थी. बचपन में कुर्सी रेस, खोखो और कबड्डी का खेल स्कूली जीवन के लोकप्रिय खेलों में शुमार थे. बड़े होने पर भले ही ये खेल हम से छूट जाते हों. पर सियासत में आज भी इन खेलों का गज़ब का क्रेज है. सभी नेता इस रेस में शुमार हैं.

जिन लोगों ने अपने चाइल्ड हुड में ये खेल नहीं खेले या देखे हों उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है. वे इसका आनंद इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के धरने के दौरान वहां चल रही म्यूजिकल चेयर रेस को देख कर ले सकते हैं. जैसे कहावत है सब का मालिक एक वैसे ही सियासत में सब का एक ही लक्ष है 7- लोक कल्याण मार्ग का बंगला. लखनऊ वाले भाई ने इसके लिए जंतर मंतर पर अनुष्ठान किया तो शांडिल्य गोत्र धारी सीधे बिना ब्रेक लगाए रेस करते हुए पुराने 7 रेस कोर्स रोड पर जा कर धमक गए.

वहां मौजूद चौकीदारों ने कहा- ऐ थामा थामा,बाबा कहां घुसे आ रहे हो ? ये घर अभी खाली नहीं हुआ है. खबर मिली तो टूटी वाले ने मन ही मन कहा पार्टनर से दगा ! इट्स अ टू मच.भैया भी नंगे पैर जंतर मंतर छोड़, दौड़ लगा वहां पहुंच गए और बुदबुदाने लगे अच्छा सिला दिया तूने मेरे .... पुलिस बल ने दोनों को सड़क से टांगाटोली कर 25 लाख की बस में डाल कर रवाना किया. ये है दिल्ली की चुनावी म्यूजिकल चेयर रेस. केजरीवाल पहले से ही जंतर मंतर पर झंडा गाड़े बैठे हैं. कुल मिला कर सब गा रहे हैं मौका मौका.

उत्तर कोरिया, चीन और रूस ने बदल दिया ईरान का सैन्य भूगोल

डॉ.ब्रह्मदीप अलूने
(अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ)

जॉर्डन में अल-अज़राक एयरबेस, प्रिंस हसन एयरबेस, किंग फैसल एयरबेस और अल-सफावी बेस जैसे अमेरिकी और अन्य रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान अब केवल मिसाइलों या ड्रोन के सीमित उपयोग तक ही नहीं रुका है, बल्कि वह अपने सैन्य अभियानों में बहुस्तरीय और समन्वित रणनीतियों का प्रयोग कर रहा है। यह घटनाक्रम आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति का एक महत्वपूर्ण संकेत है. आज किसी संघर्ष की सफलता केवल हथियारों की संख्या या उनकी मारक क्षमता से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि विभिन्न सैन्य साधनों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर क्षमताओं, ड्रोन, मिसाइलों और खुफिया तंत्र का कितनी प्रभावी ढंग से समन्वय किया जाता है. यही कारण है कि हाइब्रिड वॉरफेयर और मल्टी-लेयर्ड अटैक जैसी अवधारणाएं आधुनिक युद्ध की केंद्रीय रणनीति बनती जा रही हैं.

दरअसल पश्चिम एशिया में हाल के वर्षों में यदि किसी देश की सैन्य क्षमता ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है, तो वह ईरान है. कभी हथियारों और सैन्य तकनीक के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहने वाला यह देश आज लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, अत्याधुनिक ड्रोन, आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता के कारण क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली सैन्य शक्तियों में गिना जाता है. जॉर्डन में हमलों में जिस रणनीति का प्रदर्शन हुआ, उसे सैन्य विशेषज्ञ मल्टी-लेयर्ड अटैक कहते हैं. इस रणनीति के तहत सबसे पहले बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन और कम लागत वाले हवाई प्लेटफॉर्म छोड़े जाते हैं. इनका उद्देश्य विरोधी देश के रडार और वायु रक्षा प्रणाली को व्यस्त रखना होता है.

इसके बाद लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से कमांड सेंटर, एयरबेस, विमान हैंगर और अन्य रणनीतिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है. मिसाइल और ड्रोन का यह संयुक्त उपयोग पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि उन्हें एक साथ अनेक दिशाओं से आने वाले अलग-अलग प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है. यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ. इसके पीछे लगभग तीन दशकों का सैन्य, तकनीकी और औद्योगिक विकास छिपा है. इस विकास में ईरान के स्वदेशी अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन उतना ही बड़ा योगदान चीन, उत्तर कोरिया और रूस के साथ विकसित हुए सहयोग का भी रहा. इन तीनों देशों ने ईरान को सीधे अत्याधुनिक हथियार देने के बजाय ऐसी तकनीक, औद्योगिक क्षमता, प्रशिक्षण और रक्षा अवसंरचना उपलब्ध कराई, जिसने उसे आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति में बदल दिया.चीन ने ईरान को आधुनिक रक्षा उद्योग विकसित करने में सबसे व्यापक तकनीकी सहयोग प्रदान किया. पश्चिमी देशों के विभिन्न आकलनों के अनुसार, चीनी मूल के सेंसर, माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कंपोजिट सामग्री, मशीन टूल्स, नेविगेशन उपकरण तथा मिसाइल ईंधन से संबंधित औद्योगिक सामग्री वर्षों से ईरान की रक्षा उत्पादन प्रणाली तक पहुँचती रही है. इन तकनीकों ने ईरान को केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें स्वयं विकसित और बड़े पैमाने पर निर्मित करने की क्षमता प्रदान की.

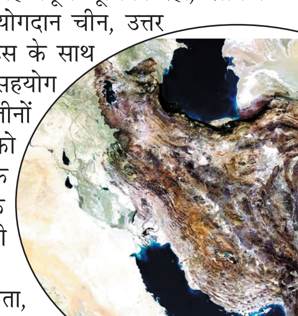

ईरान के शाहेद ड्रोन कार्यक्रम के विकास में भी चीनी औद्योगिक अनुभव और वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक्स की भूमिका की चर्चा अंतरराष्ट्रीय रक्षा विश्लेषणों में होती रही है. आधुनिक ड्रोन युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, संचार प्रणाली और नेविगेशन तकनीक उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी स्वयं ड्रोन की संरचना. यही कारण है कि आज ईरान कम लागत वाले लेकिन प्रभावी ड्रोन विकसित करने में सफल रहा है, जिनका उपयोग रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया के संघर्षों तक देखा गया है.

यदि चीन ने ईरान के रक्षा उद्योग को तकनीकी आधार दिया, तो उत्तर कोरिया ने उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की बुनियाद रखी. 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने ईरान को स्कड-बी और स्कड-सी जैसी मिसाइलें उपलब्ध कराईं. बाद में इन्हीं तकनीकों के आधार पर ईरान ने शाहाब-1, शाहाब-2 और शाहाब-3 जैसी मिसाइलों का विकास किया. उत्तर कोरिया की नोडोंग मिसाइल तकनीक ने ईरान की मध्यम दूरी की मिसाइल क्षमता को नई दिशा दी. इसके अतिरिक्त मिसाइल इंजन, प्रक्षेपण प्रणाली, मोबाइल लॉन्चर, उत्पादन तकनीक, परीक्षण प्रक्रियाएँ और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर कोरिया का सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता है. समय के साथ ईरान ने इन तकनीकों को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने अनुसंधान और उत्पादन क्षमता के अनुरूप विकसित भी किया. परिणामस्वरूप आज उसकी कई मिसाइलें मूल उत्तर कोरियाई डिजाइनों से काफी आगे निकल चुकी हैं. रूस का योगदान मुख्य रूप से वायु रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अंतरिक्ष तकनीक और सामरिक सहयोग के क्षेत्र में दिखाई देता है. रूस ने ईरान को स-300 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, रडार तकनीक, हेलीकॉप्टर, उपग्रह सहयोग और आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क विकसित करने में सहायता दी.

छात्र आंदोलन का इतिहास

लक्ष्मण सिंह
पूर्व सांसद

प्राचीन भारत से लेकर अगर हम छात्र आंदोलन का इतिहास देखें तो हमें भारत की आजादी का प्रथम आंदोलन जो 1857 में हुआ था ,उसके बीच तक कहीं भी कोई छात्र आंदोलन का इतिहास नहीं मिलता है , उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन में राजा लड़े थे उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र भी थे ! गुरु का सम्मान प्राचीन भारत में होता था और जो शासक थे वो गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करते थे, सुदामा और कृष्णा की मित्रता इसका उदाहरण है ! यह भी एक कारण रहा प्राचीन भारत में छात्र कभी भी उतेजित नहीं हुए क्योंकि उन्हें गुरु अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखते थे !

मुगल शासन में और अंग्रेजों के शासन काल में केवल प्रतिष्ठित परिवार के लोगों को ही शिक्षा का अधिकार था और आंबेडकर जी जैसे कई नेताओं को सभी को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था तब देश की आजादी के बाद शिक्षा का अधिकार स्वतंत्र भारत में संविधान के अंतर्गत, सबको दिया गया ! 1970 के दशक में जय प्रकाश जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था इमरजेंसी के बाद जो कांग्रेस सरकार के विरुद्ध था और वह एक सकारात्मक आंदोलन था और चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी,परन्तु वो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाना चाहते थे नहीं का पाए क्योंकि जनता पार्टी टूट गई और उनके टूटने के बाद कई दल और बन गए और शिक्षा की स्थिति नहीं सुधार पाई !शनै: शनै: हमने देखा कि गुरु का सम्मान छात्रों द्वारा कम होने लगा, क्या कारण रहे? मैं उसमें नहीं जानता ,परन्तु ऐसा होता रहा और जो शासन में थे ,उन्होंने छात्रों का राजनीतिक उपयोग करना शुरू कर दिया जिसके कारण गुरु और शिष्य के बीच का जो अटूट संबंध था वो कमजोर होता चला गया क्योंकि नेता इन दोनों के बीच में आ गए और गुरु ने जब देखा कि छात्र शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं तो उन्होंने भी छात्रों से दूरी बना ली और अब छात्र और गुरु का संबंध केवल शिक्षा के कक्ष तक ही रह गया और जो वर्षों से गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी वो समाप्त होती गई और आज लगभग शून्य है क्योंकि छात्र आज पूर्णत: नेताओं की गिरफ्त में हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा ही वो अधिकतर करते हैं और इसीलिए आज ये हाल शिक्षा का हो गया है कि धनवान अच्छी उच्च शिक्षा पा रहे हैं और मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के छात्र सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हैं !

आज डॉक्टर बनना है तो लगभग 50 लाख से एक करोड़ रुपया निजी मेडिकल कॉलेज को डोनेशन ऐसा होता रहा और जो शासन में थे , उन्होंने छात्रों का राजनीतिक उपयोग करना शुरू कर दिया जिसके कारण गुरु और शिष्य के बीच को सड़क से संसद तक संघर्ष करना पड़ रहा है ! प्राचीन ग्रीस में एक बहुत बड़े चिंतक ,विद्वान हुए थे जिन्हें हिंदी में हम' सुकरात' के नाम से जानते हैं, वो छात्रों को कहा करते थे कि राजा से सवाल करना सीखो, तभी तुम्हारी दशा सुधरेगी, उस समय ग्रीस का राजा इतना नाराज हुआ कि उसने सुकरात को मरवा दिया था !आज प्रजातंत्र है और छात्रों को अपनी आवाज उठाने, प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ! मैं जब भी ग्रामों या छोटे शहरों में जाता हूं तो आज भी छात्र प्रारंभ में सहमे से रहते हैं ! उन्हें चर्चा और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है तब वो सवाल पूछते हैं और चर्चा करते हैं, अधिकांश तो छात्रों को केवल नेताजी का स्वागत करने को कहा जाता है, जिसके पश्चात नेताजी का संबोधन होता है और कार्यक्रम का समापन हो जाता है, छात्रों से संवाद नहीं होता है ! नेता और अधिकारियों को छात्रों से संवाद अवश्य करना चाहिए और इसकी गति भी बढ़ानी चाहिए ! शिक्षक पालक संघ की व्यवस्था भी है जहां छात्र के माता पिता शिक्षकों से संवाद करते हैं परन्तु छात्र को कम बोलने दिया जाता है !

महिलाओं की समायोजन प्रवृत्ति पर योग का प्रभाव

डॉ. लता पाठक
(योगाचार्या 7 वेलनेस कोच)

आज की भारतीय महिला केवल परिवार की धुरी ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की सशक्त आधारशिला भी है। वह घर, परिवार, कार्यस्थल और सामाजिक दायित्वों के बीच निरंतर संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है. बदलती जीवनशैली, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, समय का अभाव और अनेक अपेक्षाओं के बीच मानसिक एवं भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आज प्रत्येक महिला के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे समय में समायोजन की क्षमता ही उसे तनावमुक्त, आत्मविश्वासी और सफल जीवन की ओर अग्रसर करती है.

समायोजन का अर्थ केवल परिस्थितियों से समझौता करना नहीं है, बल्कि स्वयं को इस प्रकार विकसित करना है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रख सके. योग इसी समायोजन क्षमता को विकसित करने का एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और प्रभावशाली माध्यम है. योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है. यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने का अभ्यास नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के मध्य संतुलन स्थापित करने की संपूर्ण जीवन-पद्धति है. नियमित योगाभ्यास से मन शांत होता है, तनाव कम होता है, भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है तथा व्यक्ति में धैर्य, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण का विकास होता है. यही गुण महिलाओं को परिवार, समाज और कार्यस्थल पर बेहतर समायोजन स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं.

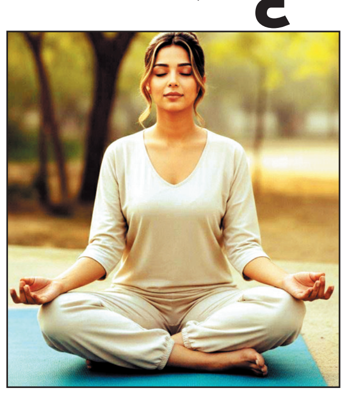

कार्यरत महिलाओं पर योग का प्रभाव- कार्यरत महिलाओं को कार्यालय की जिम्मेदारियों के साथ-साथ परिवार, बच्चों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है. दोहरी जिम्मेदारियों के कारण उनमें तनाव, थकान, अनिद्रा, चिंता और भावनात्मक दबाव की संभावना अधिक रहती है. नियमित योग, प्राणायाम एवं ध्यान से तनाव हार्मोन कम होते हैं, कार्यक्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है तथा मानसिक संतुलन बना रहता है. परिणामस्वरूप वे अपने कार्यस्थल और परिवार दोनों में अधिक सफलतापूर्वक समायोजन स्थापित कर पाती हैं.

गैर-कार्यरत महिलाओं पर योग का प्रभाव- अक्सर यह माना जाता है कि गृहिणियों का जीवन अपेक्षाकृत सरल होता है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है. घरेलू कार्यों का निरंतर दबाव, परिवार के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी, स्वयं के लिए समय का अभाव तथा भावनात्मक अपेक्षाएँ उन्हें भी मानसिक रूप से प्रभावित करती हैं. योगाभ्यास उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा, आत्मसम्मान, धैर्य और मानसिक शांति का विकास करता है. इससे उनका पारिवारिक वातावरण अधिक सुखद, संतुलित और सौहार्दपूर्ण बनता है.

तुलनात्मक अध्ययन:- कार्यरत एवं गैर-कार्यरत महिलाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नियमित योगाभ्यास करने वाली दोनों श्रेणियों की महिलाओं में समायोजन क्षमता, तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन का स्तर अधिक पाया जाता है. कार्यरत महिलाओं में योग का प्रभाव मुख्यत: कार्यकुशलता, समय प्रबंधन, मानसिक दृढ़ता एवं निर्णय क्षमता पर अधिक दिखाई देता है, जबकि गैर-कार्यरत महिलाओं में इसका प्रभाव पारिवारिक सामंजस्य, आत्मसंतोष, मानसिक प्रसन्नता भावनात्मक संतुलन पर अधिक स्पष्ट रूप से देखा जाता है. इस प्रकार योग दोनों वर्गों की महिलाओं के जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है.

महिलाओं की समायोजन क्षमता बढ़ाने हेतु अनुशंसित योगासन एवं प्राणायाम- नियमित योगाभ्यास महिलाओं के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है. निम्नलिखित योगासन एवं प्राणायाम विशेष रूप से लाभकारी हैं—

योगासन: ताड़ासन – आत्मविश्वास, शरीर का संतुलन एवं मानसिक स्थिरता बढ़ाता है. **वृक्षासन** – एकाग्रता, धैर्य एवं भावनात्मक संतुलन विकसित करता है. **भुजंगासन** – रीढ़ को सशक्त बनाकर थकान एवं तनाव कम करता है. **मार्जरी-व्याघ्रासन** – रीढ़ की लचक बढ़ाता है तथा मानसिक तनाव दूर करता है. **सेतु बंधासन** – हार्मोनल संतुलन एवं मानसिक शांति के लिए लाभकारी है. **पश्चिमोत्तानासन** – मन को शांत कर आत्मनियंत्रण विकसित करता है. **बद्धकोणासन** – महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य एवं श्रोणि क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी है. **शवासन** – सम्पूर्ण शरीर एवं मन को गहन विश्राम प्रदान करता है.